Media Release

दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद ने कॉर्पोरेट्स के साथ किया बैठक का आयोजन

- **3000** दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हुए उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में किया गहन विचार-विमर्श

नई दिल्ली/अहमदाबाद, **21** सितंबर, **2023**- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के सहयोग से कॉर्पोरेट्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यह बैठक कॉर्पोरेट्स की 'सीएसआर' गतिविधियों के तहत दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 'सुनिश्चित आजीविका को सपोर्ट, एक्टिवेट और निर्मित' करने के मकसद से आयोजित की गई।

अपनी तरह के इस अनूठे कार्यक्रम में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस, ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ. सुनील शुक्ला और ईडीआईआई में परियोजना विभाग (कॉर्पोरेट) के निदेशक डॉ. रमन गुजराल ने भी भाग लिया। उनके साथ डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख कॉर्पोरेट संस्थाओं के सीएसआर अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान दिव्यांगजनों को लेकर बड़े पैमाने पर समाज को संवेदनशील बनाने और उनकी बेहतरी के प्रभावी उपाय शुरू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही, दिव्यांगजनों के लिए **3,000** नए उद्यमों की स्थापना सुनिश्चित करने की दिशा में भी किए जाने वाले उपायों पर भी विमर्श किया गया। इनमें से **1,500** टैक्नोलॉजी-संचालित और **1,500** सामान्य उद्यम हैं।

इस निर्णायक गोलमेज बैठक में सरकार, कॉर्पोरेट्स और संस्थानों के बीच प्रभावी तालमेल के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने पर विचार-मंथन किया गया। चर्चाएँ स्थायी उद्यम निर्माण के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के विशिष्ट उद्देश्यों के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। साथ ही, समाज में उनके पूर्ण समावेश को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए बुनियादी ढांचे, दिव्यांग जनों के बारे में धारणा, पर्यावरण, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में बेहतर प्रथाओं को अपनाने पर भी चर्चा की गई। उनके लिए कामकाज का एक बेहतर और अनुकूल माहौल तैयार करने और ऐसे व्यावसायिक अवसरों की एक सूची तैयार करने पर भी विचार किया गया, जिसकी सहायता से दिव्यांगजन अपना उद्यम स्थापित करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। इस बात पर भी मंथन किया गया कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लक्ष्यों के साथ दिव्यांगजनों के कल्याण को कैसे जोड़ा जाए और समाज में उस पेशेवर अलगाव को कैसे तोड़ा जाए जो दिव्यांगों को कम वेतन वाली नौकरियों में धकेल देता है।

गंभीर चर्चाओं और निष्कर्षों के आधार पर, भाग लेने वाले कॉर्पोरेट्स ने सहयोग के कुछ प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की। दिव्यांगों के लिए **3000** उद्यम बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहचानी गई कुछ गतिविधियों में शामिल हैं- दिव्यांगों के सामुदायिक एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान; दिव्यांग किशोरों के लिए गहन जीवन कौशल; दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक अवसरों की सोर्सिंग; दिव्यांगजनों के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएँ और क्रेडिट लिंकेज सपोर्ट। साथ ही, सहयोग के इन क्षेत्रों में बेरोजगार दिव्यांगों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए

उद्यमी विकास-सह-परामर्श कार्यक्रम (ईजीसीपी) का आयोजन और दिव्यांग-आधारित उद्यमों को सपोर्ट करने के लिए और सूक्ष्म कौशल उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) को भी शामिल किया गया।

दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने अपने भाषण की शुरुआत इस संदेश के साथ की कि भारत चंद्रमा पर पहुंच गया है लेकिन आज भी दिव्यांग लोगों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में, हमारा दृष्टिकोण समावेशी है लेकिन बुनियादी ढाँचा अभी भी समावेशी नहीं है। उन्होंने सीएसआर के माध्यम से सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने, अपस्किलिंग, दिव्यांगों को ऋण और सलाह प्रदान करने, 'कूलेबिलिटी फैक्टर' के बाद नौकरियों की मैपिंग, उचित आवास प्रदान करने, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए छुट्टियां प्रदान करने सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सपोर्ट करने के मुद्दे उठाते हुए बातचीत की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने कंपनियों के वितरण नेटवर्क में संदेश फैलाने और दिव्यांगजनों को काम पर रखने पर जोर दिया और दिव्यांगजनों के प्रति बड़े पैमाने पर समाज के दृष्टिकोण में बदलाव पर भी बल दिया।

दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के उप महानिदेशक श्री किशोर बी. सुरवाडे ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने, सहायक उपकरण, दिव्यांगजनों को छात्रवृत्ति और पुनर्वास सेवाओं सहित विभाग की विभिन्न पहलों और योजनाओं के बारे में चर्चा की।

इस दौरान दिव्यांगजनों के कौशल और रोजगार के लिए नए लॉन्च किए गए डीईपीडब्ल्यूडी पीएम दक्ष पोर्टल की विशेषताओं को समझाते हुए एक वीडियो दिखाया गया।

ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ. सुनील शुक्ला ने कहा, "अब समय आ गया है कि हम, एक समाज के रूप में, समावेशी विकास के बारे में सोचें, जिसमें दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दिव्यांगजनों को उचित रूप से प्रशिक्षण और सहायता मिले और ऐसी प्रक्रिया को नियमित आधार पर पूरा करना होगा। हमें उनके लिए स्थायी व्यावसायिक अवसरों और उद्यमशीलता से जुड़ी व्यावहारिक संभावनाओं का भी पता लगाना होगा। इसके साथ ही सभी स्तरों पर समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यस्थलों और सामाजिक ढांचे के विभिन्न स्तरों पर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना भी महत्वपूर्ण है।"

ईडीआईआई में परियोजना विभाग (कॉर्पोरेट) के निदेशक डॉ. रमन गुजराल ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए कॉर्पोरेट्स द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए बताया कि ईडीआईआई ने अब तक **266** कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से **8,533** दिव्यांगों को प्रशिक्षित किया है, जिससे **1,247** उद्यमों की स्थापना हुई है। ईडीआईआई के परिसर में दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र (सीईडीए) कार्यरत है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक रक्षा निदेशालय, गुजरात राज्य विकलांग (दिव्यांग) वित्त और विकास निगम, गुजरात सरकार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

सम्मेलन कक्ष में उपस्थित अधिकारियों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के अग्रणी लोगों के बीच एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया। एक घंटे तक चली गोलमेज चर्चा में पहुंच, सहायता और सहायक उपकरण, जॉब मैपिंग, उद्यमिता के अवसर और विकलांगता संवेदीकरण और दिव्यांगों के लिए एआई जैसे संबंधित विषय शामिल थे।

धन्यवाद ज्ञापन एवं ग्रुप फोटो के साथ बैठक समाप्त हुई।

About Entrepreneurship Development Institute of India (EDII)

The Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), Ahmedabad was set up in 1983 as an autonomous and not-for-profit Institute with support of apex financial institutions - the IDBI Bank Ltd., IFCI Ltd., ICICI Bank Ltd. and State Bank of India (SBI). The Government of Gujarat pledged twenty-three acres of land on which stands the majestic and sprawling EDII Campus. EDII has been recognized as the CENTRE OF EXCELLENCE by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. of India. The Institute has also been listed as the Institute of National Importance by the Education Department, Govt. of Gujarat. EDII operates across the country through its seven regional offices and PAN India project offices. It has international affiliates in Cambodia, Laos, Myanmar Vietnam, Uzbekistan and Rwanda. For more information visit: www.ediindia.org

About Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), under Ministry of Social Justice & Empowerment, GoI was set up in May 2012 with the aims to facilitate empowerment and inclusion of the persons with disabilities and acts as a nodal agency to look after all development agenda of Persons with Disabilities (Divyangjan).Empowerment of persons with disabilities is an inter-disciplinary process, covering various aspects namely, prevention, early detection, intervention, education, health, vocational training, rehabilitation and social integration. The vision of the Department is to build an inclusive society in which equal opportunities are provided for the growth and development of Persons with Disabilities so that they can lead productive, safe and dignified lives.

For more information, contact:

Nirupam Banerjee, Adfactors PR: 9825984727
Hiral Oza, Adfactors PR: 7043901987